सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक

जोरदार देशव्यापी संयुक्त संघर्ष चलाओ

तपन सेन

सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक गत 2 से 4 दिसंबर 2002 तक हरियाणा के हिसार में संपन्न हुयी। बैठक स्थल का नाम शांति घटक नगर रखा गया था। बैठक ने देश के मजदूर, वर्ग तथा दूसरी शोषित-पीड़ित श्रेणियों को आह्वान किया गया कि वे भाजपा के नेतृत्ववाली एन डी ए सरकार के जनविरोधी,राष्ट्रविरोधी तथा फासीवादी हमलों के खिलाफ अपने देशव्यापी संघर्ष को और आगे ले जाएं। बैठक ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया कि सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा संयुक्त रूप से तय किए गए संघर्ष के आगामी कार्यक्रमों के लिए देशभर से जबर्दस्त लामबंदी हो। संघर्ष के इन आगामी कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों ने 8 जनवरी को देश भर में सत्याग्रह आयोजित करने तथा गिरफ्तारियां देने और 26 फरवरी को संसद मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया है। संघर्ष की ये कार्रवाइयां देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों के रूप में की जा रही हैं,जो कि इन कार्रवाइयों के बाद संघर्ष का अगला चरण होगा।

प्रभावशाली रैली

कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले एक दिसंबर को पुराने गवर्मेंट कालेज मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था,जिसमें करीब 15000 मजदूरों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्य प्रशासन ने इस बात की अनेक कोशिशें की थी कि यह रैली न होने पाए। राज्य के अनेक हिस्सों में पुलिस ने उन वाहनों को रोकने की कोशिश की जिनमें मजदूर रैली में भाग लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन मजदूरों के उत्साह के सामने पुलिस प्रशासन की ये सारी कोशिशें नाकाम रही और हजारों की संख्या में मजदूर जुलूसों के रूप में दस-दस किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके रैली स्थल तक पंहुचे। रैली में सबसे पहले हरियाणा राज्य सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष बलबीर दहिया ने झज्जर जिले के दुलीना में पुलिस की मिलीभगत से विश्व हिंदू परिषद तथा बंजरग दल के गुंडों द्वारा पांच दलितों को बर्बरतापूर्वक पीट-पीटकर मार डालने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में सिरसा में जाने-माने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की भी कड़ी निंदा की गयी थी। उनकी हत्या हरियाणा की शासक जुंडली से जुड़े गुंडों द्वारा की गई है।

हरियाणा राज्य सी आइ टी यू के अध्यक्ष एस एन सोलंकी ने रैली की अध्यक्षता की। रैली को संबोधित करते हुए सी आइ टी यू के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोहम्मद अमीन ने हरियाणा के मजदूर वर्ग का उसके बहादुरीपूर्ण संघर्षों के लिए अभिनंदन किया। राज्य का मजदूर वर्ग ये संघर्ष राज्य प्रशासन तथा मालिकान के गुंडों के बर्बर दमन का सामना करके चला रहा है। मोहम्मद अमीन ने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की जनपरस्त तथा मजदूरपरस्त नीतियों के बारे में बताया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही सारी सीमाओं तथा बाधाओं के बावजूद ये नीतियां लागू की जा रही हैं। मोहम्मद अमीन का कहना था कि राज्य के मजदूरों, किसानों

श्रम कानूनों में परिवर्तन किस के हित में होगा ?

श्रम मंत्रालय के सूत्रों से उपलब्ध आंकड़े बनाते हैं कि वर्ष 1991 तथा 2002 के मध्य दस वर्षों की अवधि में 23 करोड़ मानव दिवसों की क्षति हुई; इनमें से हड़तालों के कारण केवल 9.20 करोड़ (केवल 39.8 प्रतिशत) जबकि तालाबंदियों के कारण 13.80 करोड़ (60.2 प्रतिशत) मानव दिवसों की क्षति हुई। वर्ष 2001-02 के आर्थिक सर्वेक्षण में 1997-2001 के मध्य की अवधि में मानव दिवसों की क्षति की सूचना दी गई है (अगले कालम में देखिये)।

ये सेवा योजक ही हैं जो श्रमिकों के साथ आक्रमक व्यवहार करते हैं और टकराव की स्थिति में उत्पन्न करते हैं जबकि उदारीकरण तथा भूमंडलीयकरण के इस युग में इसकी मार श्रमिकों पर पड़ती है; उपरोक्त आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि श्रम बाजार के 'सुधारों' से पूर्व यह स्थिति है तब 'सुधारों' के लागू हो जाने के पश्चात् श्रमिकों का भाग्य कैसा होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।

मानव दिवसों की क्षति (मिलियन में)

वर्ष	हड़ताले	तालाबंदियां	कुल
1997	6.3	10.7	17.0
1998	9.4	12.7	22.1
1999*	10.6	16.2	26.8
2000*	12.0	16.8	28.8
2001@	2.5	10.8	13.3

*(*अंतरिम @ सितम्बर तक)*

तथा जनतांत्रिक जनता के संयुक्त संघर्षों के बल पर ही वाम मोर्चा सरकार सत्ता में आयी थी और पिछले 25 वर्षों से कायम है। उन्होंने शोषित-उत्पीड़ित जनता की संयुक्त कार्रवाईयों को और मजबूत करने का आह्वान किया ताकि केंद्र की सांप्रदायिक सरकार और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में चल रही उसके सहयोगियों की सरकारों की विभाजनकारी जनविरोधी नीतियों को मात दी जा सके और एक जनपरस्त विकल्प विकसित किया जा सके।

रैली को संबोधित करते हुए सी आइ टी यू अध्यक्ष ई बालानंदन ने नव-उदारवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों के विरोध के बारे में बताया जो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उनका कहना था कि हमें इस संघर्ष को और व्यापक बनाने के लिए पहलकदमी करनी चाहिए। उन्होंने देश की शोषित-उत्पीड़ित जनता की एकता को भंग करने के लिए वाजपेयी सरकार द्वारा की जा रही बदतरीन सांप्रदायिक साजिशों को बेनकाब करने और उनके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत भी बताई।

सी आइ टी यू महासचिव एम के पंधे ने रैली को संबोधित करते हुए मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह राज्य की सांप्रदायिक तथा जातिवादी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करे,जिन्हें चौटाला सरकार की शह हासिल है। उनका कहना था कि ये शक्तियां जनता को विभाजित कर रही हैं। सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किए गए संघर्ष के आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने हरियाणा के मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि इन सभी कार्यक्रमों में जबर्दस्त लामबंदी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करे।

जिन अन्य लोगों ने रैली को संबोधित किया उनमें शामिल हैं: सी आइ टी यू सचिव के हेमलता तथा तपन सेन, हरियाणा राज्य सी आइ टी यू के नेतागण सतबीर सिंह, प्रभात सिंह, अवतार सिंह तथा जसबीर कौर,सर्व कर्मचारी संघ,हरियाणा के नेता आर सी जग्गा. किसान सभा के नेता पृथ्वी सिंह और सी पी आइ (एम) राज्य सचिव इंद्रजीत सिंह।

अध्यक्षीय भाषण

सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक 2 दिसंबर को हिसार के पंचायत भवन में शुरू हुयी। इसे सूर्यनारायण राव मंच नाम दिया गया था। सूर्यनारायण राव सी आइ टी यू के वयोवृद्ध नेता थे,जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में ई बालानंदन ने सिलीगुड़ी में गत अप्रैल में संपन्न हुयी सी आइ टी यू जनरल कांऊसिल की बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रमुख घटनाविकास के बारे में बताया। उन्होंने नव उदारवादी साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ विश्व स्तर पर हड़तालों और संघर्षों के उठते ज्वार का जिक्र करते हुए कहा कि यह लामबंदी विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व थोपने की अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ भी है। उनका कहना था कि इराक के खिलाफ अमरीका के युद्धोन्माद की यूरोप, लातिनी अमरीका तथा एशिया के तमाम प्रमुख शहरों की शोषित-उत्पीड़ित जनता के अलावा खुद अमरीका के शोषित-उत्पीड़ित जनता ने निंदा की है। बालानंदन का कहना था कि विश्व स्तर पर इस बढ़ते साम्राज्यवाद विरोध से हमारे देश में वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर उसके द्वारा साम्राज्यवाद के सामने ज्यादा से ज्यादा आत्म समर्पण किए जाने के खिलाफ भारतीय जनता के आंदोलन को बल मिलेगा।

संघ परिवार के फासीवादी सांप्रदायिक हमलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बालानंदन ने मजदूरों को लामबंद करने और मनुष्य विरोधी सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियों को अलग-थलग करने तथा उन्हें मात देने के फौरी काम पर जोर दिया।

विनाशकारी नीतियां

महासचिव की रिपोर्ट में एम के पंधे ने प्रमुख राजनीतिक घटना विकास पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में उनका कहना था कि केंद्र सरकार राजनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह अवसरवादी भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही साथ सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले आए दिन की बात हो गयी है। इसी समय भाजपा का नेतृत्व सांप्रदायिक दंगे भड़काने की आपराधिक कार्रवाई में लगा हुआ है जैसे कि उसने गुजरात में किया। ऐसा वे सत्ता में बने रहने के लिए अपने क्षुद्र राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी किसी राजनीतिक ताकत ने मानवता के प्रति ऐसा घृणित अपराध नहीं किया था जैसा संघ परिवार और उसके संगठनों ने गुजरात नरसंहार के दौरान किया,सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। उनका कहना था कि यह फासीवादी सांप्रदायिक हमला मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और मजदूर वर्ग को पूरी दृढ़ता से इसके खिलाफ लड़ना होगा।

रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था पर नव उदारवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के भंयकर असर के बारे में विस्तार से बताया गया था। अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में आ रही गिरावट से यह स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में दसवीं योजना में 8 फीसद की विकास दर का जो शोर मचाया जा रहा है, वह जनता के साथ क्रूर मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। रिपोर्ट का कहना था कि अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, जबकि लोग भुखमरी से मर रहे हैं, वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है,ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगारहीनता की स्थिति है,गरीबी और बदहाली बढ़ती ही जा रही है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीति के दीवालियापन को बेनकाब कर देती हैं। आर्थिक नीति का स्पष्ट राष्ट्रविरोधी दुराग्रह सरकार की उन करतूतों में सामने आ रहा है जिनके अन्तर्गत लाभ कमानेवाली

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में मिट्टी के मोल बेचा जा रहा है, निजी हितों में राष्ट्रीय दौलत को लुटाया जा रहा है,फिर चाहे ये निजी हित विदेशी हों या देशी। निजीकरण का हर मामला एक घोटाला बन कर सामने आया है। हाल ही घोषित किए गए मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सुधारों के लिए पहलकदमी का लक्ष्य विदेशी पूंजी और भारतीय कारपोरेट लाबी को और ज्यादा उदार रियायतें देना है और ऐसा मजदूरों के प्राविडेंट फंड तथा छोटी बचतों पर ब्याज की दरें कम करके और आम आदमी की बचतों को सट्टेबाजाराना काम के लिए शेयर बाजार की ओर मोड़ देने के जरिए किया जायेगा।

एक तरफ व्यापक गरीबी तथा अंधाधुंध आयात उदारीकरण और दूसरी तरफ गलत नीतियों के चलते कृषि लागतों की बढ़ती कीमतों के चलते किसानों को अपनी फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं और छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसान इससे सबसे अधिक पीड़ित हैं। खेत मजदूरों की हालत और बदतर है। सबसे अपशकुनकारी लक्षण यह है कि भूमिहीनता में इजाफा होना शुरू हो गया है और छोटी तथा मध्यम दर्जे की जोतें बड़े भूस्वामियों के हाथों में जा रही हैं, फिर ऐसा चाहे ठेके के जरिए हो रहा हो या पूरी तरह उन्हें बेचने के जरिए। सूखे की स्थिति ने इस भयंकरता को और बढ़ा दिया है और वाजपेयी सरकार उदासीन बनी हुयी है।

ऐसी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ मजदूरों तथा समाज के दूसरे तमाम तबकों के लोगों के संघर्षों के उठते ज्वार में देशव्यापी व्यापक एकता सामने आयी है। विभिन्न राज्यों में,वहां की राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही इन्हीं नीतियों के खिलाफ प्रतिरोधपूर्ण संघर्ष बढ़ रहा है। ट्रेड यूनियन तथा श्रम अधिकारों में भारी कटौतियां करने की घृणित साजिशें चल रही हैं। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें,वाजपेयी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित ही हैं और ये श्रम कानूनों को बदलने के लिए आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ही हैं। ये सिफारिशें ऐसी हैं जो मालिकान को हायर एंड फायर की पूरी छूट देती हैं। एकतरफा तौर पर मजदूरों की सेवा शर्तें बदलने की सिफारिश करती है। हर काम के लिए ठेके पर मजदूर रखने की छूट देती हैं और हड़ताल के अधिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगाती हैं। वास्तव में यह मजदूरवर्ग पर दासता की स्थिति थोपने की ही कोशिश है। ट्रेड यूनियन आंदोलन को शासक वर्गों की इस घृणित साजिश का एकजुट होकर प्रतिरोध करना होगा।

संयुक्त संघर्ष

बैठक ने ''संयुक्त संघर्ष तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन के सांगठनिक सुदृढ़ीकरण'' के मुद्दे पर विचार विमर्श किया और इस मसले पर सी आइ टी यू के रुख तथा परिप्रेक्ष्य का मसौदा तैयार किया। तपन सेन ने सी आइ टी यू सेक्रेटेरियट द्वारा तैयार किए गए मसौदे के आधार पर बहस की शुरूआत की। इसमें 1970 के बाद से देश में संयुक्त आंदोलन के विकास एवं सी आइ टी यू के अनुभवों को रखा गया था। ट्रेड यूनियनों की बहुलता के बावजूद शासक वर्ग की शोषणकारी नीति के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की लाइन जोरदार ढ़ंग से आगे बढ़ाने के द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन में ठोस एकता हासिल की गयी है। संघर्षों के जरिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के संयुक्त मंच को धीरे-धीरे व्यापक बनाया गया है और अभी नव उदार भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ देश के लगभग सभी ट्रेड यूनियन केंद्र एकसाथ हैं।

सी आइ टी यू को मजदूरवर्ग की एकता को नुकसान पंहुचानेवाली तोड़फोड़ और विभाजनकारी शक्तियों के प्रति खबरदार रहना होगा। इस बात पर जोर दिया गया कि मजदूरवर्ग की एकता की रक्षा करने के लिए सांप्रदायिकता तथा जातिवाद की शक्तियों के खिलाफ सचेत संघर्ष चलाने की फौरी जरूरत है।

वर्तमान संदर्भ में मजदूरवर्ग को एकजुट करने के प्रयासों को एकजुट देशव्यापी संघर्ष की स्थितियां पैदा करने के लिए जोरदार ढ़ंग से निचले स्तरों तक ले जाना होगा। शासक वर्गों की नीतियों का असली चेहरा दिखाने के लिए जागरूकता पैदा करने की खातिर सी आइ टी यू द्वारा स्वतंत्र पहलकदमियां करने की फौरी जरूरत है। इसके साथ ही साथ आम मजदूरों के बीच इन नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच (एन पी एम ओ) को भी फिर से सक्रिय करने की जरूरत दोहरायी गयी ताकि सरकार की राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में जनता के तमाम तबकों को लामबंद किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर सभी ट्रेड यूनियनों का कन्फेडरेशन बनाने के विचार को भी लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को प्रभावी ढ़ंग से हाथ में लेने में सक्षम बनने के लिए संगठन को वैचारिक तथा सांगठनिक दोनों ही स्तरों पर मजबूत तथा सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है।

रिपोर्ट पर हुयी बहस में 26 सदस्यों और विशेष बहस में 18 सदस्यों ने भाग लिया। बहस में समीक्षा अवधि के दौरान हुयी गतिविधियों का आत्मालोचनात्मक परीक्षण किया गया और मौजूदा संघर्ष को जुझारूपन की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हर स्तर पर व्यापक पहलकदमियों की जरूरत पर जोर दिया गया।

बैठक ने सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ये प्रस्ताव हैं: इराक पर युद्ध थोपने की अमरीकी साजिशों के खिलाफ,सांप्रदायिकता के खतरे पर,दीवालिया नीतियों के खिलाफ और अधिकारों की रक्षा के लिए चलनेवाले संघर्षों पर,हरियाणा के संघर्षरत मजदूरवर्ग का अभिनंदन करते हुए,आंगनवाड़ी मजदूरों तथा सहायकों की मानदेय राशि बढ़ाने पर और ''जूट पैकेजिंग मैटिरियल्स एक्ट 1987'' को संरक्षण देने पर। □